



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234747  
CG-DL-E-01042022-234747

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944

No. 171]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

यूको बैंक, प्रधान कार्यालय : कोलकाता

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2021

**फा. सं. एचो/ईसटी/2021-22/297.**—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श तथा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

- (1) ये विनियम यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 2020 कहे जाएंगे।
  - (2) जब तक संबंधित विनियमों में अन्यथा न कहा गया हो, ये विनियम नवंबर, 2012 माह के प्रथम दिवस से प्रभावी माने जाएंगे, सिवाय उसके जो इन विनियमों में अन्यथा उल्लेखित हो।
2. यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके बाद कथित विनियम के रूप में उल्लिखित) में विनियम 3 में -  
खंड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा-

(एफ) "परिवार" से अभिप्राय अधिकारी का/की पति/पत्नी, पूर्णतया आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले और विधिपूर्वक गोद लिए हुए बच्चों सहित), पूर्णतया आश्रित चालीस फ्रीसदी अथवा इससे अधिक अपंगता के साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग भाई/बहन, विधवा पुत्रियाँ एवं आश्रित तलाक़शुदा अथवा अलग रह रहीं पुत्रियाँ, अविवाहित अथवा

परित्यक्त अथवा पति से अलग रह रही अथवा विधवा बहनें तथा अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित एवं आमतौर पर साथ रह रहे माता-पिता तथा विवाहित महिला अधिकारी के मामले में उसके नैसर्गिक माता-पिता अथवा सास-ससुर शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं।

**स्पष्टीकरण :** "पूर्णतया आश्रित" का अभिप्राय परिवार के ऐसे सदस्य से होगा जिसकी आय 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक न हो और जहां परिवार के पूर्ण आश्रित सदस्य माता-पिता हैं, किसी भी माता-पिता की आय या माता-पिता दोनों की कुल आय यदि 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक है तो माता-पिता दोनों को पूर्णतया अधिकारी पर आश्रित नहीं माना जाएगा।"

3. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 4 में, उप-विनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, यथा :-

**"(6) दिनांक 01 नवंबर, 2012 से प्रभावी प्रत्येक श्रेणी के समक्ष विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नवत होंगे:-**

(क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = रु. 76520 – 2120/4 – 85000

वेतनमान VI = रु. 68680 – 1960/4 – 76520

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = रु. 59170 – 1650/2 – 62470 - 1800/2 – 66070

वेतनमान IV = रु. 50030 – 1460/4 – 55870 – 1650/2 – 59170

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = रु. 42020 – 1310/5 – 48570 - 1460/2 – 51490

वेतनमान II = रु. 31705 – 1145/1 – 32850 – 1310/10 – 45950

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I = रु. 23700 – 980/7 – 30560 – 1145/2 – 32850 – 1310/7 – 42020

**स्पष्टीकरण :** दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को प्रभावी वेतनमान द्वारा शासित प्रत्येक अधिकारी का दिनांक 01 नवंबर, 2012 को इस उप विनियम में निर्धारित वेतनमान में चरण दर चरण आधार पर नियतन किया जायेगा, संबंधित वेतनमान में प्रथम चरण और उसके आगे सदृश चरणों में तथा वेतनवृद्धि सामान्य तौर पर प्रतिवार्षिक तिथि होगी जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो।

**(7) उप विनियम (1), (2), (3), (4), (5) और (6) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।**

**(8) 1.11.2012 से प्रभावी अधिकारियों को निम्नवत विशेष भत्ता भुगतान किया जाएगा:**

वेतनमान I-III – मूल वेतन का 7.75% + उसपर प्रयोज्य मंहगाई भत्ता

वेतनमान IV-V – मूल वेतन का 10% + उसपर प्रयोज्य मंहगाई भत्ता

वेतनमान VI-VII – मूल वेतन का 11% + उसपर प्रयोज्य मंहगाई भत्ता

नोट: प्रयोज्य मंहगाई भत्ता सहित विशेष भत्ता सेवानिवृत्ति फ़ायदों यथा एनपीएस, पीएफ और ग्रेच्युटी सहित पेंशन में नहीं गिने जाएंगे।

#### 4. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 5 में, -

(i) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होंगे, यथा:-

“(1) विनियम 4 के उप-विनियम (6) के प्रावधानों के अधीन, दिनांक 1 नवम्बर, 2012 को और से, वेतनवृद्धि निम्नलिखित के अधीन प्रदान की जाएगी, यथा:-

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (6) में वर्णित विभिन्न वेतनमानों में निर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वार्षिक आधार पर उपचित होंगी और ये उस महीने की पहली तारीख को प्रदान की जाएंगी, जिसमें यह देय होती होगी।

(ख) वेतनमान I एवं वेतनमान II के अधिकारियों को उनके संबंधित वेतनमानों के उच्चतर स्तर तक पहुंचने के एक वर्ष पश्चात उनकी कार्य-कुशलता वर्ग को पार करने के अध्यक्षीन केवल नीचे खंड (ग) में विनिर्दिष्ट के अनुसार अगले उच्चतम वेतनमान में गतिरोध वेतनवृद्धि सहित आगे की वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी।

(ग) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I के अधिकारी, जो उच्चतम वेतनमान के उच्चतर स्तर पर पहुँचने के पश्चात खंड (बी) के संबंध में मध्य प्रबंधन श्रेणी हेतु वेतन के वेतनमान II में चले गए हों, वे अपनी सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्णता पर चार गतिरोध वेतनवृद्धि, जिनमें से पहले दो प्रत्येक रु.1310/- के एवं अगले दो प्रत्येक रु.1460/- के लिए पात्र होंगे।

(घ) मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के अधिकारी जो उच्चतम वेतनमान के उच्चतर स्तर पर पहुँचने के पश्चात खंड 5(बी) के संबंध में मध्य प्रबंधन श्रेणी हेतु वेतन के वेतनमान III में चले गए हों, वे अपनी सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्णता पर प्रत्येक रु.1460/- की तीन गतिरोध वेतनवृद्धियों के लिए तथा तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्ति पश्चात दो वर्ष रु.1460/- चौथे गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते यह कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने तीसरे गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात दो अथवा अधिक वर्ष पूर्ण कर चुके हों, 01.05.2015 से प्रभावी चौथे गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे।

(ङ.) वास्तविक मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के अधिकारी (जो मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में नियुक्त अथवा पदोन्नत हुए हैं) वे अपनी सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्णता पर प्रत्येक रु.1460/- की तीन गतिरोध वेतनवृद्धियों के लिए तथा ऐसे अधिकारी जिन्होंने 01.05.2015 तक तीसरे गतिरोध वेतनवृद्धि जारी किए जाने के पश्चात दो अथवा अधिक वर्ष पूर्ण कर चुके हों, चौथे गतिरोध वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे तथा चौथे गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के दो वर्ष पश्चात रु.1460/- पांचवें गतिरोध वेतनवृद्धि बशर्ते यह कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने चौथे गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात दो वर्ष पूर्ण कर चुके हों, 01.05.2015 से प्रभावी पांचवें गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे।

(च) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान- IV के अधिकारी वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के तीन वर्ष पश्चात 01 मई 2015 से प्रभावी रु.1650/- की एक गतिरोध वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे।

बशर्ते यह कि ऐसा अधिकारी जिसने दी गई पदोन्नति इंकार किया हो, उसे ऐसे वेतनवृद्धि की अनुमति नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण** – इस उपनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में प्रदान की गई ऐसी वेतनवृद्धियों का तात्पर्य पदोन्नति नहीं होगी और अधिकारी को उसके वास्तविक पद के अनुसार ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व होंगे।

(ii) उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (एफ़) के पश्चात एवं नोट के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड डाला जाएगा, यथा:-

“(जी) 01.11.2012 को एवं इसके बाद से, अन्य बातों के समान रहते हुए व्यावसायिक योग्यता वेतन की राशि निम्नानुसार संशोधित होगी:-

## तालिका

(1)	(2)
जिन्होंने सीएआइआइबी- भाग I/जेएआइआइबी परीक्षा उत्तीर्ण की हो	वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात रु.670/- प्रति माह।
जिन्होंने सीएआइआइबी के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हो	वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात रु.670/- प्रति माह। वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात रु.1680/- प्रति माह।

बशर्ते यह कि यदि कोई अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के पश्चात जेएआइआइबी/सीएआइआइबी (एक अथवा दोनों भाग) की अर्हता प्राप्त करता है तो व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तिथि से एवं व्यावसायिक योग्यता वेतन की परवर्ती किस्त का भुगतान, व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त के भुगतान की तिथि के आधार पर जारी किया जाएगा।”

(iii) उप-विनियम (3) में, खण्ड (ई) के पश्चात एवं नोट के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, यथा:-

“(एफ) दिनांक 1 नवम्बर, 2012 को एवं इसके बाद से, अन्य बातों के समान रहते हुए, आवास किराया भत्ते के साथ स्थिर वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दर से दिया जाएगा तथा ये संपूर्ण सेवाकाल के लिए स्थिर रहेगा:

## तालिका

वेतनवृद्धि घटक (रु.)	वेतनवृद्धि घटक पर दिनांक 01.11.2012 से मंहगाई भत्ता (रु.)	कुल देय स्थिर वैयक्तिक वेतन जहां बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है (रु.)
(1)	(2)	(3)
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

## नोट :-

(i) इस उप-विनियम के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) के अंतर्गत कॉलम (3) की तालिका में इंगित स्थिर वैयक्तिक भत्ता/स्थिर वैयक्तिक वेतन, उन अधिकारियों को भुगतान किया जाएगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) आवास किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए स्थिर वैयक्तिक भत्ता/स्थिर वैयक्तिक वेतन, खण्ड (एफ) की तालिका के कॉलम (1) एवं (2) में निर्दिष्ट राशि एवं संबद्ध अधिकारी कर्मचारी द्वारा आहरित आवास किराया भत्ता के योग की राशि होगी जब विनियम 4 के उप-विनियमों (2), (3), (4), (5) एवं (6) में निर्दिष्ट संगत वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर ली गई हो।

(iii) वे अधिकारी जो 1.11.93 को अथवा इससे पहले से बैंक की सेवा में थे, वेतन के अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात स्थिर वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे।

(iv) 1 नवंबर, 1999 को एवं से स्थिर वैयक्तिक वेतन जारी किए जाने के क्रम में उप-विनियम (2) के तहत स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार स्थिर वैयक्तिक वेतन जारी करने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि जहां व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किस्त जो पूर्ववर्ती प्रावधानों के कारण हो और उसे एक वर्ष के लिए स्थानांतरित कर दिया गया हो तथा 1 नवंबर, 1999 को अथवा इसके पश्चात जारी करना निर्धारित हो,

तो यह अधिकारी को उसी तारीख को एवं से तथा व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि हो, 1 नवंबर, 2000 को जारी होगी।

(v) स्थिर वैयक्तिक भत्ते/ स्थिर वैयक्तिक वेतन की वेतनवृद्धि घटक सेवानिवृत्ति लाभों के लिए श्रेणीबद्ध होंगे।

(vi) कोई अधिकारी जो उक्त खण्ड (क) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर चुका है, वह वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात, उक्त खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) अथवा (च) में किए उल्लेख के अनुसार स्थिर वैयक्तिक भत्ता/स्थिर वैयक्तिक वेतन की राशि आहरित करेंगे।

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में उप-विनियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, यथा:-

“(6) 01.11.2012 को एवं इसके बाद से अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के त्रैमासिक औसत में 4440 बिंदुओं में प्रत्येक 4 बिंदु के बढ़ने अथवा घटने के लिए वेतन का 0.10% मंहगाई भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए -

मंहगाई भत्ता के लिए “वेतन” से तात्पर्य गत्यारोध वेतनवृद्धि एवं विशेष भत्ते सहित मूल वेतन से होगा।

विनियम 5 के उप-विनियम (2) के (ग), (घ), (ङ), (च) एवं (छ) में विनिर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता भत्ता/ व्यावसायिक योग्यता वेतन, मंहगाई भत्ते की गणना में किए जाएंगे।

6. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 22 में -

(i) उप-विनियम (1) एवं (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होंगे, यथा:-

“(1) 1 नवम्बर, 2012 को एवं इसके बाद से-

(क) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो वह जिस वेतनमान में हैं उसके प्रारंभिक मूल वेतन के 0.75% के बराबर अथवा आवास के लिए मानक किराया में से, जो भी कम हो, की समान राशि उनसे वसूल की जाएगी।

(ख) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं की गई हो, वे निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर आवास किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, यथा:

#### तालिका

कार्यस्थल	आवास किराया भत्ता
(1)	(2)
“ए” श्रेणी के प्रमुख शहर एवं ग्रुप ए में परियोजना केन्द्र	वेतन का 9.0%
वर्ग- I के अन्य स्थान एवं समूह बी एवं गोवा राज्य में परियोजना केन्द्र	वेतन का 8.0%
अन्य स्थान	वेतन का 7.0%

बशर्ते यह कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है, तो वे जिस वेतनमान में हैं उसके प्रारंभिक मूल वेतन के 0.75% से अधिक की वास्तविक राशि, जिसका किराए के रूप में उनके द्वारा भुगतान किया गया हो, के समान आवास किराया भत्ता देय होगा जो कॉलम (2) के उपर्युक्त तालिका में देय आवास किराया भत्ते के अधिकतम 150% के अधीन होगा।

**नोट:** अधिकारी के स्वामित्व आवासीय लागत से जुड़े आवास किराया भत्ता हेतु उनका दावा आवास किराया भत्ता के 150% तक प्रतिबंधित होगा।

## 7. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 23 में-

(क) उप-विनियमन (1), (2), (3), (4) एवं (5) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होंगे, यथा:-

“(1) 01.11.2012 को एवं इसके बाद से यदि कोई अधिकारी नीचे की कॉलम 1 की तालिका में विनिर्दिष्ट स्थान में कार्यरत है तो वह कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट स्थानों से संबंधित दरों पर नगर क्षतिपूर्ति भत्ता देय होगा:

तालिका

स्थान (1)	दरें (2)
वर्ग- I स्थान एवं गोवा राज्य	मूल वेतन का 4.0% अधिकतम रु. 870/- प्रति माह के अध्यक्षीन
(बी) 5 लाख एवं अधिक जनसंख्या वाले स्थान तथा राज्य की राजधानी और चंडीगढ़, पुडुचेरी एवं पोर्टब्लेयर	मूल वेतन का 3.0% अधिकतम रु. 600/- प्रति माह के अध्यक्षीन

(2) 1.11.2012 को एवं इसके बाद से, विशेष क्षेत्र भत्तों की दरें इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी।

“(3) 01.11.2012 को एवं इसके बाद से, यदि कोई अधिकारी समूह “ए” अथवा समूह “बी” के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजना क्षेत्र में कार्यरत है तो, वह समूह “ए” अथवा समूह “बी” में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार रु. 400/- प्रति माह अथवा रु. 350/- प्रति माह की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा।

(4) 1.06.2015 को एवं इसके बाद से, यदि कोई अधिकारी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक अथवा अधिक बच्चे उनके पूर्ववर्ती स्थान के स्कूल और कॉलेज में पढते हैं, तो वे स्थानांतरण अर्थात् बाद वाले स्थान पर रिपोर्ट करने की तारीख से शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक उन सभी बच्चों के संबंध में रु.1100/- प्रति माह की दर से मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्तों के पात्र होंगे परंतु यदि सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर देते हों तो यह भत्ता भी समाप्त हो जायेगा।

(5) 1.06.2015 को एवं इसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय परिलब्धियों को प्राप्त करने अथवा बैंक के वेतन के अतिरिक्त वेतन के 7.75% की दर से अधिकतम रु. 4000/- प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते उसी स्थान पर पदस्थापना होने पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते हैं, को लेने का विकल्प दे सकता है।

बशर्ते यदि वह ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त होता है, जो उसी स्थान पर स्थित है जहाँ वह प्रतिनियुक्ति से तुरंत पूर्व पदस्थ था तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु. 2000/- प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

आगे यह भी कि बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने वेतन का 4% अधिकतम रु. 2000/- प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए पात्र होगा।

(ख) उप-विनियमन (8) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(8) 1.11.2012 को और इसके बाद से यदि कार्य दिवस का कार्यकाल न्यूनतम 2 घंटों के अंतराल में विभक्त होता है, तो अधिकारी रु.200/- प्रति माह की दर से स्प्लिट ड्यूटी भत्ते के लिए पात्र होगा।

(ग) उप-विनियम (10) में, -

(ए) “नवम्बर 2007 की पहली तारीख” के आंकड़े, अक्षर और शब्द “नवम्बर, 2012 की पहली तारीख” से प्रतिस्थापित किए जाएंगे.

(बी) तालिका के लिए निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी :

## तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम उँचाई वाले स्थान और मेरकरा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम रु. 750/- प्रति माह
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम उँचाई वाले स्थान पर	वेतन का 2.5% अधिकतम रु. 1000/- प्रति माह
(iii) 3000 मीटर एवं उससे अधिक उँचाई वाले स्थान पर	वेतन का 5% अधिकतम रु. 2000/- प्रति माह

8. उपर्युक्त कथित विनियमों के विनियम 24 में-

(i) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:

(1) 1.11.2012 को एवं इसके बाद से, स्वयं और अपने परिवार के लिए चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु कोई अधिकारी इस प्रकार व्यय की गई राशि के संबंध में स्वयं के प्रमाण पत्र एवं दावा की गई राशि के लेखा विवरण के आधार पर नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट दावा राशि हेतु पात्र होगा, यथा :-

## तालिका

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु. 8000 प्रति वर्ष अथवा व्यय की गई राशि, जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु. 9050 प्रति वर्ष अथवा व्यय की गई राशि, जो भी कम हो

नोट :-

एक अधिकारी को उपयोग न की गई चिकित्सा सहायता राशि को इस प्रकार संचित करने की अनुमति होगी जो कि किसी भी समय ऊपर उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी;

वर्ष 2012 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति 2 माह अर्थात् नवम्बर, 2012 तथा दिसम्बर, 2012 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाएगी।

(1क) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार एक अधिकारी अपने और अपने परिवार के लिए चिकित्सा बीमा सुविधा के लिए पात्र होगा।"

9. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 25 में उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा:

"(2) उप विनियम (1) में कुछ भी निहित होते हुए दिनांक 1 नवम्बर, 2012 से किसी भी अधिकारी को वह जिस वेतनमान में हो, उसके प्रारम्भिक मूल वेतन के 0.75% के समान राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, का अधिकारी द्वारा भुगतान के आधार पर अधिकारी को आवास उपलब्ध कराने का बैंक का खुला अधिकार होगा।

बशर्ते यदि किसी अधिकारी को इस आवास पर फर्नीचर की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है तो जिस वेतनमान में वह अधिकारी हो, उसके प्रारम्भिक मूल वेतन का 0.15% और वसूल किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि यदि इस प्रकार का आवास बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया है, तो बिजली, पानी, गैस एवं संरक्षण का व्यय अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।

10. उपर्युक्त विनियम के विनियम 33 में, उप विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(4) दिनांक 1 जून 2015 को एवं इसके बाद से, साधिकार अवकाश दो सौ सत्तर (270) दिनों से ज्यादा संचय नहीं किया जा सकता सिवाय वहाँ जहाँ अवकाश आवेदन किया गया हो और इसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

बशर्ते कि साधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम दो सौ चालीस (240) दिनों तक प्रतिबंध होगा।

बशर्ते आगे यह कि, साधिकार अवकाश उपयोग करने के इच्छुक अधिकारी को इस प्रकार के अवकाश उपयोग करने के लिए सामान्यतः कम से कम 15 दिनों पहले सूचना देनी होगी।

11. उपर्युक्त विनियम के विनियम 34 में, उप विनियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप विनियम जोड़ा जाएगा, यथा:-

“(4) दिनांक 1 जून 2015 को एवं इसके बाद से, तीस (30) दिनों तक विशेष विमारी अवकाश, किसी अधिकारी को उसकी सेवा की सम्पूर्ण अवधि में केवल एक बार किडनी/अंग दान करने के लिए दिया जाए।”

12. उपर्युक्त विनियम के विनियम 36 में, उप विनियम (2) एवं (3) के लिए, निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापन किया जाएगा, यथा:-

“(2) दिनांक 25 मई, 2015 से प्रभावी, किसी संतानहीन महिला अधिकारी द्वारा विधिक रूप से एक वर्ष से कम उम्र के बच्चा को गोद लेने के लिए सेवा के दौरान एक बार निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार छह माह की अधिकतम अवधि के लिए अवकाश दिया जा सकता है।

(i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए ही अवकाश दिया जाएगा।

(ii) उचित विधिक प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे को गोद लिया जाना चाहिए तथा ऐसी छुट्टियों की स्वीकृति हेतु अधिकारी द्वारा बैंक को दत्तक विलेख प्रस्तुत करना चाहिए।

(iii) सारोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के मामले में जैविक माता को भी छुट्टी उपलब्ध होगी।

(iv) सेवा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान 12 माह की पूर्ण पात्रता के भीतर छुट्टी का उपभोग होना चाहिए।

(3) दिनांक 25.05.2015 से प्रभावी, 12 माह की पूर्ण अवधि के भीतर हिस्टेरेक्टमी (शल्य चिकित्सा से बच्चेदानी निकाला जाना) के मामले में अधिकतम 60 दिनों की छुट्टी भी दी जा सकती है।

(4) मातृत्व अवकाश, जो मूल वेतन पर होगा, किसी महिला अधिकारी को किसी एक अवसर पर 6 माह से अधिक नहीं एवं उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान 12 माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा।

बशर्ते यह कि 12 माह की कुल अवधि के भीतर गर्भस्राव या गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय अवसान के मामले में भी अवकाश दी जा सकती है।

(5) दिनांक 01.06.2015 से प्रभावी, दो तक जीवित बच्चे वाले पुरुष अधिकारी कार्मिक अपनी पत्नी के प्रसव के दौरान 15 दिनों के पितृत्व अवकाश हेतु पात्र होंगे। आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के अवकाश के साथ यह अवकाश जोड़ा जा सकता है।

बशर्ते यह कि अवकाश बच्चे के जन्म की तारीख से 15 दिन पूर्व अथवा 6 माह तक लिया जा सकता है।

13. उपर्युक्त विनियम के विनियम 38 में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापन किया जाएगा, यथा:-



“(38) अवकाश की समाप्ति - नीचे दिए गए के सिवाय, किसी अधिकारी का जमा किया गया अवकाश उसके इस्तीफा देने, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, बरखास्तगी, पदच्युति अथवा सेवा समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा:

बशर्ते यह कि जहां कोई अधिकारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है, वह किसी अवधि की परिलब्धियों के समान धनराशि, उसके द्वारा संचित 240 दिनों की साधिकार अवकाश से ज्यादा नहीं पाने के लिए पात्र होगा।

बशर्ते आगे यह कि जहां कोई अधिकारी बैंक की सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया है, जो सजा के रूप में शामिल है, वह किसी भी अवधि की उपलब्धियों के बराबर राशि का भुगतान पाने का पात्र होगा, जो दो सौ चालीस दिनों के विशेषाधिकार अवकाश से अधिक नहीं होगा जो उसने जमा किया था:

बशर्ते यह कि जहां कोई अधिकारी अपनी सेवाकाल में मर जाता है तो वहां उसके विधिक प्रतिनिधि को किसी अवधि की परिलब्धियों के समान धनराशि, उसकी मृत्यु की तारीख तक संचित 240 दिनों के साधिकार अवकाश से ज्यादा नहीं, देय होगा।

बशर्ते यह भी कि जहां कोई अधिकारी 1 अप्रैल, 2001 को अथवा इसके बाद सेवा से इस्तीफा देता है तो उसे विनियम 20 के उप-विनियम (2) के अनुसार नियत नोटिस देने के पश्चात उसे उसकी सेवा समाप्ति की तारीख तक संचित ऐसे अवकाशों की आधी मात्रा, अधिकतम 120 दिन, साधिकार अवकाश के संबंध में परिलब्धियों के समान धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।

14. उपर्युक्त विनियम के विनियम 41 में,

(i) के उप विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापन किया जाएगा, यथा:-

“(I) 1 नवंबर 2012 को एवं इसके बाद से, जहां कहीं भी किसी अधिकारी को ड्यूटी पर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, यथा :-

(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी ट्रेन से प्रथम वर्ग या 2-स्तरीय वातानुकूलित शयनयान से यात्रा करने के पात्र होंगे :

बशर्ते कि वह हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय या सार्वजनिक हित की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई हो;

(ख) मध्यम प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी ट्रेन से प्रथम वर्ग या 2-स्तरीय वातानुकूलित शयनयान से यात्रा करने के पात्र होंगे :

बशर्ते कि वह हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) कर सकता है यदि यात्रा की जाने वाली दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक हो:

बशर्ते आगे यह भी कि वह कम दूरी के लिए भी हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय की आवश्यकताओं या सार्वजनिक हित की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने की अनुमति दी गई हो।

(ग) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी ट्रेन से वातानुकूलित प्रथम वर्ग या हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा करने के पात्र होंगे :

(घ) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी हवाई यात्रा या ट्रेन से नहीं जुड़े स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकते हैं बशर्ते कि दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो:

बशर्ते कि जब दो स्थानों के बीच की दूरी का एक बड़ा हिस्सा हवाई यात्रा या ट्रेन द्वारा कवर किया जा सकता है, तो बाकी की दूरी सामान्य रूप से कार द्वारा तय की जानी चाहिए;

(ड.) किसी अन्य अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है;

(च) किसी भी श्रेणी या वेतनमान के अधिकारी सड़क या हवाई यात्रा या ट्रेन से नहीं जुड़े स्थानों के बीच डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन द्वारा यात्रा करने के पात्र होंगे होगा;

(ii) उप-विनियम (4) में, खंड (ए) और (बी) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा: -

‘(ए) दिनांक 1 जून, 2015 को एवं इसके बाद से, नीचे दी गयी तालिका के कॉलम (1) में दी गयी संगत श्रेणी अथवा वेतनमान के अधिकारी इस तालिका के कॉलम (2) में दी गयी संगत दर के अनुसार ‘प्रतिदिन’ विराम भत्ता (हॉल्टिंग) के लिए पात्र होंगे, यथा:-

#### तालिका

अधिकारी की श्रेणी/वेतनमान	मेट्रो (रु.)	‘ए’ श्रेणी के बड़े शहर (रु.)	एरिया- I (रु.)	अन्य स्थान (रु.)
वेतनमान VI एवं इससे ऊपर के अधिकारी	1800	1300	1100	950
वेतनमान IV एवं V के अधिकारी	1500	1300	1100	950
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	1300	1100	950	800

आगे यह कि यदि कुल अनुपस्थिति अवधि आठ घंटों से कम परंतु चार घंटों से अधिक है तो विराम (हॉल्टिंग) भत्ता उपर्युक्त दर का आधा देय होगा।

**स्पष्टीकरण** – विराम (हॉल्टिंग) भत्ते की गणना के उद्देश्य से “प्रतिदिन” से तात्पर्य हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान हेतु रिपोर्टिंग समय से एवं अन्य मामलों में निर्धारित प्रस्थान से प्रारम्भ कर पहुंचने के वास्तविक समय तक प्रत्येक चौबीस घंटे की अवधि अथवा उसका भाग माना जाएगा जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे, “प्रतिदिन” से कम है, का अभिप्राय यह होगा कि यह आठ घंटे से कम अवधि का नहीं है।

15. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापन किया जाएगा, यथा:

“(3) दिनांक 01.06.2015 को एवं इसके बाद से, अधिकारी स्थानांतरण पर पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा इत्यादि से संबंधित खर्चों के लिए निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट एकमुश्त राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, यथा:-

#### तालिका

श्रेणी/वेतनमान	राशि
(1)	(2)
शीर्ष कार्यपालक एवं वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी (वेतनमान IV एवं इससे ऊपर के अधिकारी)	रु. 20,000
मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी (वेतनमान III तक के अधिकारी)	रु. 15,000

16. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 44 में, उपनियम (3) में, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापन किया जाएगा, यथा:-

“(3) चार वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, अधिकारी दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में एकबार अपने अधिवास स्थान की यात्रा करने के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) हेतु पात्र होगा।

विकल्पतः वह दो वर्षों के एक ब्लॉक में अपने अधिवास स्थान तथा दो वर्षों के अन्य ब्लॉक में भारत के किसी भी स्थान का सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा कर सकता है।

यह कि दिनांक 1 जून, 2015 से, अधिकारी 4 वर्ष के ब्लॉक अथवा 2 वर्ष के ब्लॉक के दौरान किसी समय, जैसा मामला हो, विकल्पतः अपना एलटीसी (अधिवास स्थान की यात्रा को छोड़कर) उपभोग छोड़ सकते हैं तथा उसका नकदीकरण कर सकते हैं जिस पर कप्रश्रे-वेतनमान- I एवं मप्रश्रे-वेतनमान- II व III के अधिकारियों हेतु 4500 किमी (एक तरफ) दूरी तथा वप्रश्रे-वेतनमान-IV एवं इससे ऊपर के अधिकारियों हेतु 5500 किमी (एक तरफ) दूरी तक अपनी श्रेणी में ट्रेन द्वारा यात्रा करने के लिए उचित किराये के बराबर राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे।

यह कि 1 जून, 2015 से अधिकारी अपने एलटीसी के नकदीकरण चुनने का विकल्प का दावा स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए केवल एक बार उस ब्लॉक/अवधि के दौरान करेगा जिसमें इस तरह के नकदीकरण का लाभ उठाया गया हो। अवकाश किराया रियायत (एलएफसी) उपभोग करने के समय साधिकार अवकाश के नकदीकरण की सुविधा एलटीसी सुविधा के नकदीकरण के समय भी उपलब्ध होगी।

(3ए) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) उपभोग करने के लिए अधिकारी की यात्रा का माध्यम एवं श्रेणी वही होगा जो सामान्यतः अधिकारी के स्थानांतरण पर यात्रा के लिए पात्रता होती है तथा अधिकारी द्वारा उपभोग किए जाने वाले यात्रा रियायत (एलटीसी) की अन्य नियम एवं शर्तों के अध्यक्षीन एवं समय-समय से बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार होगा।

यह कि 1 मई, 2010 से कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I का अधिकारी, अवकाश यात्रा रियायत सुविधा का उपयोग करते समय वह न्यूनतम किराया इकाँनामी श्रेणी में हवाई यात्रा के लिए पात्र होगा एवं ऐसे मामले में वास्तविक हवाई किराया अथवा ट्रेन से तय की गई यात्रा की दूरी के लिए एसी प्रथम श्रेणी का किराया, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसी प्रकार मध्य प्रबंधन श्रेणी के वेतनमान II व वेतनमान III के अधिकारियों के लिए भी अवकाश यात्रा रियायत सुविधा के उपयोग के समय यही नियम लागू होंगे, जहां दूरी 1000 किमी से कम हो।”

17. कथित विनियमन की अनुसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी:

### अनुसूची

(विनियम 23 के उप विनियम (2) का संदर्भ लें)

दिनांक 1 नवम्बर, 2012 से अधिकारी नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट विशेष क्षेत्र भत्ते के भुगतान हेतु तब तक पात्र होगा जब तक कि ये प्रावधान वापस नहीं लिए जाते अथवा इनमें पूर्णतः या आंशिक रूप से आशोधन नहीं किया जाता है, यथा:

### तालिका

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु. 24,000/- से कम वेतन	रु. 24,000/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिजोरम (ए) चिम्पतुइपुइ जिला तथा लुंगली जिले में लुंगली शहर से 25 किमी से अधिक दूरी वाले क्षेत्र	2000	2600
	(बी) लुंगली शहर से 25 किमी से दूरी वाले क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगली जिला	1600	2100
	(सी) संपूर्ण आईजोल जिला	1200	1500

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु. 24,000/- से कम वेतन	रु. 24,000/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	नागालैंड	1600	2100
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (ए) उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार एवं नरकोण्डम द्वीपसमूह	2000	2600
	(बी) दक्षिण अंडमान (पोर्टब्लेयर सहित)	1600	2100
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	2000	2600
6.	असम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा (ए) त्रिपुरा के दुर्गम इलाके	1600	2100
	(बी) दुर्गम इलाकों को छोड़कर संपूर्ण त्रिपुरा	1200	1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश (ए) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाके	2000	2600
	(बी) दुर्गम इलाकों को छोड़कर संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश	1600	2100
11.	जम्मू तथा कश्मीर (ए) कठुआ जिला : निआबतबानी, लोही, मल्हार तथा मच्छोड़ी	2000	2600
	(बी) उधमपुर जिला : डुडू बसंतगढ, लेण्डरभामग इलाका, भाग 2(बी) में शामिल के अलावा अन्य इलाका	2000	2600
	कामबन की ओर से गुल तक के क्षेत्र और मोहरे तहसील में केसई की ओर से अर्नाज तक के क्षेत्र	1600	2100
	(सी) डोडा जिला : किशतवार तहसील में पडुर एवं निआबत नौगाँव के इलाके	2000	2600
	(डी) लेह जिला : जिले के सभी स्थान	2000	2600
	(इ) बारामुला जिला : (i) संपूर्ण गुरेज-निआबत, तंगधार सब डिविजन और केरन इलाका	2000	2600
	(ii) मच्छिल	1600	2100
	(एफ) पुंछ एवं राजौरी जिले : पुंछ और राजौरी एवं सुंदरबनी तथा दोनों जिलों के अन्य शहरी इलाकों को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिलों के इलाके	1200	1500
	(जी) ऐसे क्षेत्र जो उपर कॉलम (1) से (6) में शामिल नहीं किए गए हैं, परंतु जो वास्तविक नियंत्रण सीमा के 8 किमी की दूरी के भीतर हैं	1200	1500

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु. 24,000/- से कम वेतन	रु. 24,000/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
	अथवा ऐसे स्थान जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ता दिए जाने योग्य स्थान घोषित किए गए हैं।		
12.	हिमाचल प्रदेश (1) चम्बा जिला (ए) पंगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायतें: बड़गांव, बाजोल, देवलकुगटी, नयागाम और टुंडा, गाँव: ग्रामपंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटा का कनारसी गाँव	2000	2600
	(बी) भरमौर तहसील, उपर्युक्त भाग (ए) में शामिल पंचायतों एवं गाँवों को छोड़कर	1600	2100
	(सी) भाटीयात तहसील में झाण्डरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (बानीखेत सहित)	1200	1500
	(2) किन्नौर जिला : (ए) असरांग, चितकुल और हंगोकूनो/ चरांग पंचायतें, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नाथपा तथा रुपी ग्राम पंचायतें शामिल हैं, उपर्युक्त वर्णित पंचायत क्षेत्र को छोड़कर पूह सब डिविजन	2000	2600
	(बी) उपर्युक्त (ए) में शामिल इलाकों को छोड़कर संपूर्ण जिला	1600	2100
	(3) कुल्लू जिला : (ए) निरमांड तहसील का खड़गा, कुशवार एवं सरगा ग्राम पंचायत के 15/20 क्षेत्र	2000	2600
	(बी) आउटर सेराज (निरमांड तहसील में जकात-खाना तथा बरों के गाँवों को छोड़कर) आउटर सेराज तथा पंद्राबीस परगना को छोड़कर, परंतु निरमांड तहसील के जगत-खाना एवं बुरों गांव शामिल करते हुए संपूर्ण आउटर सेराज जिला	1200	1500
	(4) लाहौल तथा स्पीती जिला : लाहौल तथा स्पीती का संपूर्ण जिला	2000	2600
	(5) शिमला जिला : (ए) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र, जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपरा एवं चाडी-ब्राण्डा पंचायतें शामिल हैं।	2000	2600
	(बी) डोरा-कवर तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील एवं सराहां परगना के मुनीश, घोरी चायबिस	1600	2100
	(सी) चोपाल तहसील एवं सराहां परगना के घोरिस, पंजगांव, पत्सनाउ, नौबीस एवं तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत,	1200	1500

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु. 24,000/- से कम वेतन	रु. 24,000/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
	रामपुर तहसील का परगना बड़ाबीस, रामपुर तहसील के परगना रामपुर के कसबा रामपुर तथा घोरी नोग, शिमला टाउन तथा इसके उप नगर (ढल्ली, जटोग, कासुमपत्ती, माशेब्रा, तारादेवी और टूट)		
	(6) कांगड़ा जिला : (ए) बड़ा भांगल और छोटा भांगल के इलाके	1600	2100
	(बी) कांगड़ा जिले का धर्मशाला टाउन तथा नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, जो कि धर्मशाला टाउन में शामिल किए गए हैं – वूमन्स आईआईटी, दारी, मैकेनिकल वर्कशाप, रामनगर, चाइल्ड वेलफेयर एवं टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग कार्यालय, सकोह, लोअर सकोह का सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, एचआरटीसी वर्कशाप, साधेर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्ट्री, दारी, आई.पी.एच. सब-डिवीजन, दान, सेटलमेंट कार्यालय, शामनगर, हिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर। पालमपुर के एचपीकेवीवी कैम्पस सहित कांगड़ा जिले का पालमपुर टाउन तथा नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, जो कि पालमपुर टाउन में शामिल किए गए हैं – एच.पी. कृषि, विश्वविद्यालय कैम्पस, मवेशी विकास कार्यालय/ जर्सी फार्म, बानुरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/ इंडो जर्मन कृषि, वर्कशॉप/ एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंदला, इलेक्ट्रीकल सब-डिवीजन, लोहना, डी.पी.ओ. कॉर्पोरेशन, बुन्दल, इलेक्ट्रीकल एचपीएसईई डिवीजन, घुग्गर।	1200	1500
	(7) मंडी जिला : जोगिंदरनगर तहसील की छुहर घाटी, बागरा तहसील में थुनाग की पंचायतें, चत्री, छोटघर, गारागुशैन, गाटू, गरयास, जांजेली, जरयार, जोहर, कल्हानी, कलवान, खोलानल, लोथ, सिलीबागी, सोमाचन, थाचधर, ताची, थान, धरमपुर ब्लॉक की पंचायतें- बिंगा, कमलाह, सकलाना, तन्यार एवं तारखोला, करसांग तहसील की पंचायतें – बालीधर, बागरा, गोपालपुर, खजोल, माहोग, मेहूदी, मंज, पेखी, साइंज, सरहान एवं तिबान, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें – बोही, बट्वारा, धनीयारा, पौरा कोठी, सेरी एवं शोजा।	1200	1500
	(8) सिरमौर जिला : बानी की पंचायतें, बखाली (पाछड़ तहसील), भारोग भेनेरी (पौन्टा	1200	1500

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु. 24,000/- से कम वेतन	रु. 24,000/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
	तहसील), बिरा (नाहन तहसील), दिब्वर (पाछड़ तहसील) एवं थाना कासोगा (नाहन तहसील) तथा तांसगिरी ट्रैक्ट		
	(9) सोलन जिला : मंगल पंचायत	1200	1500
	(10) उपर्युक्त (1) से (9) में शामिल नहीं किए गए हिमाचल प्रदेश के बाकी इलाके	320	400
13.	उत्तर प्रदेश : चमोली, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी जिले के तहत इलाके	2000	2600
14.	उत्तराखंड चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग तथा चंपावत जिले के तहत इलाके	2000	2600

### स्पष्टीकारक ज्ञापन

इन विनियमों में दिए गए भूतलक्षी प्रभाव यूको बैंक के अधिकारियों के वेतन और अन्य भत्तों तथा लाभों से संबंधित हैं जो मूलभूत लाभकारी कानून है। इसलिए, इन विनियमों के उक्त प्रावधानों को भूतलक्षी प्रभाव देने से इस तरह के भूतलक्षी प्रयोग के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नरेश कुमार, महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./725/2021-22]

**नोट :** मूल विनियम, भारत के शासकीय राजपत्र भाग III, खंड 4, में अधिसूचना प्रकाशित किए गए थे एवं तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से परवर्ती संशोधन अधिसूचित किए गए थे, यथा:-

Serial number	Notification number	Notification date	Date on which published in Official Gazette
1	HO/EST/2017-18/470	26.04.2017	27.02.2018

### UCO BANK, HEAD OFFICE : KOLKATA

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2021

**F. No. HO/EST/2021-22/297.**— In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the UCO BANK, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the UCO BANK (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

- (1) These regulations may be called the UCO BANK (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2020.

- (2) Save as provided in these regulations, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012.
2. In the UCO BANK (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(f) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty per cent or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters, and parents wholly dependent on the officer and in the case of married female officer may include her natural parents or parents-in-law, but not both.

**Explanation-** “Wholly dependent” shall mean such member of the family having an income not exceeding Rs.10,000 per month and where the wholly dependent family members are parents, the income of any parent or aggregate income of both the parents if exceeds Rs.10,000 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.”

3. In regulation 4 of the said regulations, for sub-regulation (6), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(6) With effect from 1<sup>st</sup> November, 2012, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

**(a) Top Executive Grade**

Scale VII =Rs76520 – 2120/4 – 85000

Scale VI = Rs.68680 - 1960/4 – 76520

**(b) Senior Management Grade**

Scale V = Rs59170 – 1650/2 – 62470 – 1800/2 - 66070

Scale IV = Rs.50030 – 1460/4 – 55870– 1650/2 – 59170

**(c) Middle Management Grade**

Scale III = Rs42020 – 1310/5 – 48570 - 1460/2 - 51490

Scale II = Rs.31705 - 1145/1 - 32850 - 1310/10 - 45950

**(d) Junior Management Grade**

Scale I = Rs.23700 – 980/7- 30560– 1145/2– 32850– 1310/7-42020

**Explanation-**Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31<sup>st</sup> October, 2012 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1<sup>st</sup> November, 2012 on stage to stage basis, or the corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual.

(7) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5) and (6) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(8) With effect from 1<sup>st</sup> day of November, 2012, officers shall be paid Special Allowance as under:

Scale I-III: 7.75% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV-V: 10% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI-VII: 11% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

**Note:** The special allowance with applicable DA thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, viz, pension including NPS, PF and Gratuity.

4. In regulation 5 of the said regulations, -



(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (6) of regulation 4, on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (6) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching the maximum in their respective Scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher scale, shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which the first two shall be Rs.1310 each and next two Rs.1460 each;

- (d) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b) after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.1460 each for every three completed years of service and a fourth stagnation increment of Rs.1460 two years after receipt of third stagnation increment;

Provided that officers who have completed two years or more after receipt of the third stagnation increment shall be granted the fourth stagnation increment with effect from the 1<sup>st</sup> day of May, 2015;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III (those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III) shall be eligible for three stagnation increments of Rs.1460 each for every three completed years of service and fourth stagnation increment of Rs.1460 to officers who have completed two years or more after releasing third stagnation increment as on 1<sup>st</sup> May, 2015 and a fifth stagnation increment of Rs.1460 two years after receipt of fourth stagnation increment provided that the officers who have completed two years after receipt of the fourth stagnation increment shall be granted the fifth stagnation increment with effect from 1<sup>st</sup> May, 2015;
- (f) officers in Senior Management Grade Scale-IV shall be eligible for one stagnation increment of Rs.1650 three years after reaching the maximum of scale with effect from 1<sup>st</sup> May, 2015.

Provided that such increment shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

**Explanation-** Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

- (ii) in sub-regulation (2), in the *Explanation*, after clause (f) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(g) On and from 1<sup>st</sup> day of November, 2012, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below:

**TABLE**

(1)	(2)
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers – Part I	Rs.670 per month, one year after reaching maximum of the scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.670 per month, one year after reaching maximum of the scale. (ii) Rs.1680 per month, two years after reaching maximum of the scale.

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay shall be

granted from the date of acquiring such qualification, the first instalment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent instalments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first instalment of Professional Qualification Pay.

(iii) in sub-regulation (3), after the Table under clause (e), the following shall be inserted, namely:-

“(f) On and from the 1st November, 2012, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

**TABLE**

<b>Increment Component (Rs.)</b>	<b>Dearness Allowance as on 01.11.2012 on the increment components(Rs.)</b>	<b>Total Fixed Personal Pay payable where Bank's accommodation is provided (Rs.)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

**Note:**

- (i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of this sub-regulation shall be payable to those officer who are provided with Bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the table under clause (f) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2), (3), (4), (5) and (6) of regulation 4 is earned.
- (iii) Only officers who were in the service of the Bank on or before 1<sup>st</sup> November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay they are placed.
- (iv) On and from the 1<sup>st</sup> November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after 1<sup>st</sup> November, 1999, it shall be released to the officer on and from that date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1<sup>st</sup> November, 2000.

- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
  - (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) of this sub-regulation shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e) or (f) above, one year after reaching the maximum of the scale.
5. In regulation 21 of the said regulations, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(6) On and from 1<sup>ST</sup> day of November, 2012, Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.10% of Pay.

**Explanation-** For the purposes of this sub-regulation –

- (a) “Pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments plus Special Allowance;
- (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f) and (g) to the explanation in sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for Dearness Allowance.”

6. In regulation 22 of the said regulations,-

(i) for sub-regulation (1) and (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) On and from 1<sup>st</sup> day of November, 2012, -

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely-

**TABLE**

Place of Work	House Rent Allowance
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	9.0% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	8.0% of Pay
(iii) Other places	7.0% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in Column (2) of the above Table.

**Note:** The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of the House Rent Allowance as hitherto.

7. In regulation 23 of the said regulations,-

(A) for sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(1) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012, if an officer is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable :-

**TABLE**

Places	Rates
(1)	(2)
(i) Places in Area 1 and in the State of Goa	4% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.870 per month
(ii) Places with population of five lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair.	3% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.600 per month.

(2) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations.

(3) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.400 per month or Rs.350 per month according to the classification of area as Group A or Group B respectively.

(4) On and from the 1<sup>st</sup> day of June, 2015, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.1100 per month from the date he reports to the

latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1<sup>st</sup> day of June, 2015, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.4000 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place;

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum of Rs.2000 per month;

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum of Rs.2000 per month.”;

(B) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(8) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.200 per month.”;

(C) in sub-regulation (10),-

- (a) for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2007”, the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November, 2012” shall be substituted;
- (b) for the table, the following table shall be substituted, namely:-

“TABLE

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.750 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1000 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.2000 per month”

8. In regulation 24 of the said regulations, -

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(1) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012 an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of Reimbursement
(1)	(2)
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.8000 per annum or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.9050 per annum or the amount incurred whichever is less

**Note :**

- (i) An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or
- (ii) for the year 2012, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is November 2012 and December, 2012.

(IA) An officer shall be eligible for medical insurance facility for self and his family, as per the terms and conditions specified by the Board.”

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), It shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st November, 2012, a sum equal to 0.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.15 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him;

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”

10. In regulation 33 of the said regulations, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(4) On and from 1<sup>st</sup> June, 2015, Privilege Leave may be accumulated up to not more than two hundred and seventy days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to a maximum of two hundred and forty days:

Provided further that, an officer desiring to avail of privilege leave shall ordinarily give not less than fifteen days’ notice of his intention to avail such leave.”

11. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) On and from 1<sup>st</sup> June, 2015, Special Sick Leave up to thirty days may be granted to an officer once during his entire period of service for donation of kidney or organ.”

12. In regulation 36 of the said regulations, for sub-regulations (2) and (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(2) With effect from the 25<sup>th</sup> May 2015, leave may also be granted once during service to a childless female officer for legally adopting a child who is below one year of age for a maximum period of six months subject to the following terms and conditions: -

- (i) leave will be granted for adoption of only one child;
- (ii) the adoption of a child be through a proper legal process and the officer employee shall produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;
- (iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy; and
- (iv) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.

(3) With effect from the 25<sup>th</sup> day of May, 2015, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of sixty days.

(4) Maternity leave, which shall be on substantive pay, shall be granted to a female officer for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service;

Provided that within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of miscarriage or abortion or medical termination of pregnancy.

(5) With effect from 1<sup>st</sup> June 2015, male officers employees having upto two surviving children shall be eligible for fifteen days paternity leave during his wife’s confinement which may be combined with any other kind of leave except casual leave;

Provided that the leave shall be applied upto fifteen days before or upto six months from the date of delivery of the child.”

13. For regulation 38 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“(38) Lapse of Leave - Save as provided below, all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation, retirement, death, discharge, dismissal or termination:

Provided that where an officer retires from the Bank’s service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, not exceeding two hundred and forty days of privilege leave that he had accumulated:

Provided further that where an officer has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to emoluments of any period, not exceeding two hundred and forty days of privilege leave that he had accumulated;

Provided also that where an officer dies while in service, there shall be payable to his legal representatives, a sum equivalent to the emoluments for the period not exceeding two hundred and forty days of privilege leave to his credit as on the date of his death;

Provided also that where an officer resigns from service on or after 1st April, 2001 after giving due notice as in sub-regulation (2) of regulation 20, he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of one hundred and twenty days.”

14. In regulation 41 of the said regulations,

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from 1<sup>st</sup> day of November 2012, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:—

(a) An officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1<sup>st</sup> class or AC 2- tier sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(b) An officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1<sup>st</sup> class or AC 2-tier sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 Kilometers:

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(c) An officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1<sup>st</sup> class by train or by air (economy class):

(d) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kilometres:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car;

(e) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxicab or by the Bank’s vehicle;

(f) An officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail.”;

(ii) in sub-regulation (4), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(a) On and from the 1st June, 2015, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the table below shall be entitled to per diem Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grade / Scales of Officers	Metro (Rs)	Major 'A' Class Cities (Rs)	Area I (Rs)	Other Places (Rs)
(1)	(2)			
Officers in Scale VI and above	1800	1300	1100	950
Officers in Scale IV and V	1500	1300	1100	950
Officers in Scale I, II and III	1300	1100	950	800

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

**Explanation.-** For the purposes of computing Halting allowance, "per diem" shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours."

15. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) On and from the 1<sup>st</sup> day of June 2015, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Grade/Scale	Amount
(1)	(2)
Top Executive and Senior Management Grade (Officers in Scale IV and above)	Rs.20,000
Middle Management and Junior Management Grade (Officers upto Scale III)	Rs.15,000”

16. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(3) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that, he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route;

Provided further that with effect from 1st June 2015, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 4500 kilometres (one way) for officers in JMG-Scale-I and MMG – Scale II and III and 5500 kilometres (one way) for officers in SMG- Scale IV and above:

Provided also that with effect from 1st June 2015, an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3A) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance traveled whichever is less and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kilometres.”

17. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely,:-

**“SCHEDULE**

[See regulation 23 (2)]

With effect from the 1st day of November, 2012, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the table below, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Area	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs.24,000	Pay above Rs.24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Mizoram</b>		
	(a) Chimpui District and areas beyond 25 kms. From Lunglei Town in Lunglei District.	2000	2600
	b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. From Lunglei town.	1600	2100
	c) Entire Aizawl District	1200	1500
<b>2.</b>	<b>Nagaland</b>	1600	2100
<b>3.</b>	<b>Andaman and Nicobar Islands</b>		
	a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
<b>4.</b>	<b>Sikkim</b>	2000	2600
<b>5.</b>	<b>Lakshadweep Islands</b>	2000	2600
<b>6.</b>	<b>Assam</b>	320	400
<b>7.</b>	<b>Meghalaya</b>	320	400
<b>8.</b>	<b>Tripura</b>		
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
<b>9.</b>	<b>Manipur</b>	1200	1500
<b>10.</b>	<b>Arunachal Pradesh</b>		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
<b>11.</b>	<b>Jammu and Kashmir</b>		
	(a) Kathua District: NiabatBani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District:		



Sl. No.	Area	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs.24,000	Pay above Rs.24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
	(i) DuduBasantgarh, Lander BhamagIllaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(c) Doda District: Illaquas of Padder and NiabatNowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District : All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District (i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and KeranIllaqua	2000	2600
	(ii) Matchill	1600	2100
	(f) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts	1200	1500
	(g) Areas not included in (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
<b>12.</b>	<b>Himachal Pradesh</b>		
	(1) Chamba District (a) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats: Badgaun, Bajol, DeolKugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram PanchayatJagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	2000	2600
	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above.	1600	2100
	(c) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(2) Kinnaur District: (a) Asrang, Chitkul and HangoKuno/Charang Panchayats,15/20 Area comprising the Gram Panchayats of ChhotaKhamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(b) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
	(3) Kullu District: (a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(4) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(5) Shimla District :		

Sl. No.	Area	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs.24,000	Pay above Rs.24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600
	(b) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, GhoriChaibis of ParganaSarahan.	1600	2100
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of ParganaSarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, ParganaBarabis, Kasba Rampur and GhoriNog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(6) Kangra District: (a) Areas of Bara Bhangal and ChhotaBhangal	1600	2100
	(b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar.  Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500
	(7) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil- of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoos, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	1200	1500
	(8) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali, (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	(9) Solan District : Mangal Panchayat.	1200	1500
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	320	400
<b>13.</b>	<b>Uttar Pradesh:</b> Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts	2000	2600
<b>14.</b>	<b>Uttarakhand:</b>		

Sl. No.	Area	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs.24,000	Pay above Rs.24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
	Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarakashi, Rudraprayag and Champavat Districts	2000	2600”

### EXPLANATORY MEMORANDUM

The retrospective effect given in these regulations relate to the pay and other allowances and benefits to the officers of the UCO Bank and are essentially beneficial legislation. Hence, giving retrospective effect to the said provisions of these regulations will not adversely affect the interest of any person as a result of such retrospective application.

NARESH KUMAR, General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./725/2021-22]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Part-III, Section 4, and subsequently amended vide the following notifications:

Serial number	Notification number	Notification date	Date on which published in Official Gazette
1	HO/EST/2017-18/470	26.04.2017	27.02.2018